

श्री राजनारायण : श्रीमान्, हमारा निवेदन है, जैसा कि आडवाणी जी ने प्रिविलेज के बारे में कहा, आप जानते हैं कि अर्लियेस्ट अपाचीन्टी प्रिविलेज के मामले में ली जाती है . . .

श्री उपसभापति : लेकिन उन्होंने अर्लियेस्ट अपाचीन्टी ले ली और उस पर कार्य हो गया ।

श्री राजनारायण : तो इसको अर्लियेस्ट निपटाना चाहिए । कल हमने भी एक प्रिविलेज का मामला दिया है, लेकिन हमको उसका आज कोई उत्तर नहीं दिया । मैं समझता था आज उत्तर मिल जाएगा ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : Sir, I am not raising any privilege issue, but as a Member of Parliament I have to preserve my credibility. If I said something and something is contradicted and if something else comes, then I have every right to place the facts before the House so that there is no misunderstanding. I would like to draw your attention to an unstarred question . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no, Mr. Swamy. There is a procedure for it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : It is a personal explanation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : A personal explanation can be given then and there if you are present.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : I want to say . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please listen to me. I know what is a personal explanation. If something is said about you and if you are present in the House, then and there you may make a personal explanation. If you are not there, you have to take the permission of the Chairman and then only you can make it.

MOTION FOR ELECTION TO THE ANIMAL WELFARE BOARD

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH) : Sir, I beg to move the following motion :—

“That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Animal Welfare Board”.

The question was proposed.

DR. M. R. VYAS (Maharashtra) : I would like to say that we appoint Members on this Animal Welfare Board and other Boards under statutory rules and regulations. After all, Parliament is delegating somebody to be on these Boards with a view to implementing the Acts passed by Parliament. As a Member of one of the statutory bodies affiliated to this very body, I find that the money allotted is so miserable that you cannot look after the Act and also carry out the duties as a Member. I would like to draw the Minister's attention to that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

“That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Animal Welfare Board.”

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.15 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE SICK TEXTILE UNDERTAKINGS, (NATIONALISATION) ORDINANCE, 1974 (NO. 12 of 1974)—Contd.

II. THE SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL, 1974—contd.

श्री वीरेंद्र कुमार सखलंवा (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, सिक टेक्स्टाइल्स अंडरटैकिंग्स के नेशनलाइजेशन का जो यह बिल लाया गया है और उनका जो नेशनलाइजेशन किया जा रहा है उस का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ क्योंकि यह मिल्स बड़ी खराब हालत में थी और इस के कारण, उन मिलों के बार-बार बंद होने के कारण, मजदूरों के लिए अनइंफ्लायमेंट की भीषण समस्या पैदा करती थी। मध्य प्रदेश में राजनंद गांव की मिल, जिस का टैक ओवर किया गया है, उस के कारण मजदूरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसी प्रकार की इंदौर की मिल की भी यही स्थिति थी, लेकिन उपसभापति महोदय, प्रथम बात में इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि इस का कोई ठीक आधार नहीं है। किस आधार पर मिल्स का टैक ओवर कर के उन का नेशनलाइजेशन किया जायगा इस के लिए शासन ने जो आधार अपनाएँ हैं वह ठीक नहीं हैं। जो राजनंद गांव की मिल है या बरहानपुर की मिल है उससे भी खराब हालत में मध्य प्रदेश में मिलें हैं और उन को टैक ओवर नहीं किया गया है।

जब टैक ओवर वाला बिल आया था तो मैंने अमंडमेंट दिया कि जिन दो मिलों के बारे में संशोधन प्रस्तुत किया था उनकी हालत बहुत खराब है, इतनी खराब है कि वह मजदूरों का बतन तक नहीं दे सकती। वह मिल मालिक मजदूरों को पैसे दे नहीं सकते। उनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ा हुआ है कि जिसके

कारण वह मिल चला नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी उन मिलों का टैक ओवर नहीं किया गया। ये मिलें हैं मालवा मिल और कल्याण मिल। लेकिन आपने स्वदेशी मिल का टैक ओवर कर लिया है। तो ये जो सिक मिल आप कहते हैं, कैसे आप उनको सिक निर्धारित करते हैं। इसका ठीक अनुमान शासन के द्वारा अपनाया गया, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके कारण बहुत गड़बड़ है। उज्जैन की दीपवन्द मिल की हालत इतनी खराब है तो उसका टैक ओवर नहीं किया और बाद में मिल मालिकों ने उसको दूसरों को बेच दिया। गये दो सालों में भारी मुनाफा टेक्सटाइल्स मिल्स ने कमाया है और उसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति आज भी खराब दिखाई नहीं देती है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में निष्पक्षता से विचार करके मजदूरों के हितों का खयाल करते हुए उनका टैक ओवर करना चाहिए। जो मालिक मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकते, जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक प्रकार से मनेज नहीं कर सकते, ऐसी मिल्स का टैक ओवर करके शासन को ठीक प्रकार से उनको चलाना चाहिए।

दूसरे, इसके अन्दर आपने कंपेंसेशन की बात कही है। अनेक मित्रों ने कंपेंसेशन क्लेम का विरोध किया है। मैं कहूंगा कि इसका कोई बीसस दिखाई नहीं देता। यह बात ठीक है कि संविधान में संशोधन करने के बाद रीजनल कंपेंसेशन वाली बात पर कोर्ट्स के अन्दर चैलेंज करने वाली बात नहीं रही। इसको रीजनल कंपेंसेशन नहीं माना जा सकता है। उसका आधार क्या है। स्वदेशी मिल्स का कंपेंसेशन आपने 1 हजार रुपये रखा है, आईएम 100 पर तो इंदौर मिल का आपने किस आधार पर 94 लाख रुपये कंपेंसेशन रखा है। उन मिलों के बारे में, जैसे बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव है जिसकी हालत बहुत खराब है, बहुत मुश्किल से वह चल रही थी गवर्नमेंट ने उसको 69 लाख रुपये का कंपेंसेशन रखा है। बरहानपुर को 86 लाख, इंदौर मिल को 94 लाख, कल्याण-मल मिल को 90 लाख दे रहे हैं, लेकिन स्वदेशी मिल को केवल 1000 रुपये का-